बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 50

उतार-चढ़ाव भरा अनुमान

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने आगामी मॉनसून सत्र में बारिश के लगभग सामान्य होने का अनुमान प्रकट किया है। उसका यह अनुमान अन्य घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थानों से अलग है। इनमें से अधिकांश का कहना है कि इस वर्ष बारिश सामान्य से कम रहेगी। आईएमडी का अनुमान है कि वर्ष 2019 के मॉनसून सत्र (जून से सितंबर) के दौरान कुल बारिश, लंबी अवधि के औसत के 96 फीसदी तक रहेगी। यह अनुमान निजी मौसम एजेंसी स्काइमेट के 93 फीसदी (सामान्य से कम बारिश) के अनुमान से अधिक है। स्काइमेट के अलावा भी कई निजी विदेशी मौसम एजेंसियों ने ऐसे ही अनुमान प्रकट किए हैं। पूर्वानुमानों में यह असमानता शायद इसलिए नजर आ रही है क्योंकि विभिन्न एजेंसियों ने मॉनसून को नुकसान पहुंचाने वाले अल नीनो के दक्षिण पश्चिम मॉनसून पर प्रभाव को लेकर अलग-अलग अनुमान प्रकट किए हैं। मौसम पर निगाह रखने वाले अधिकांश लोग मानते हैं कि भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में बढ़ रही गर्मी के कारण उपजा यह प्रभाव अगस्त तक प्रभावी रहेगा, हालांकि मई से इसका असर कम होना शुरू हो जाएगा। परंतु, आईएमडी को लगता है कि जून के आसपास यह कमजोर पड़ जाएगा और शायद जुलाई के बाद यह मॉनसून पर कोई असर नहीं डालेगा। बहरहाल, लगभग सभी अनुमान लगाने वाले इस बात पर तो सहमत हैं कि शुरुआती दौर में कम बारिश हो सकती है और शायद अल नीनो प्रभाव के कारण मॉनसून में कुछ देरी भी हो।

एक सच ऐसा भी है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। वह यह कि लंबी अवधि के मॉनसून अनुमान बहुत भरोसेमंद नहीं होते फिर चाहे उनका स्रोत कुछ भी हो। वर्ष 2017 को छोड़ दिया जाए तो बीते पांच वर्ष में से चार बार आईएमडी और स्काइमेट दोनों के प्रारंभिक अनुमान गलत साबित हुए। दोनों एजेंसियां वर्ष 2014 और 2015 में दो वर्ष लगातार सूखे का अनुमान लगा पाने में नाकाम रहीं। चकित करने वाली बात यह है कि डेटा संग्रह की बुनियादी सुविधाएं बढ़ने और बेहतर गणन क्षमताओं के कारण एक ओर जहां आईएमडी की अल्प से मध्यम अवधि की मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं में काफी सुधार हुआ है, वहीं दीर्घावधि के अनुमान के बारे में यह बात लागू नहीं होती।

हालांकि आईएमडी ने जोर देकर कहा है कि इस वर्ष मॉनसूनी बारिश का वितरण बेहतर होगा और यह बारिश खरीफ की फसल के लिए लाभदायक साबित होगी लेकिन फिर भी यह अनुमान अपरिपक्व नजर आता है। यह बात स्काइमेट के पूर्वानुमानों से भी मेल नहीं खाती है। आईएमडी सामान्य तौर पर बाद में जारी होने वाले अपडेट में मॉनसूनी बारिश की अवधि और विस्तार के बारे में बात करता है। ये अपडेट उस समय जारी होते हैं जब बारिश का मौसम चल रहा होता है। कृषि की बात करें तो उसके लिए बारिश की मात्रा से अधिक उसका विस्तार मायने रखता है। बहरहाल, जहां तक देश की समग्र अर्थव्यवस्था की बात है, उसमें मॉनसून का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। इसकी कई वजह हैं। उदाहरण के लिए सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान अब महज 14 से 15 फीसदी रह गया है। व्यापक कृषि क्षेत्र की बात करें तो फसली खेती जो मॉनसून से सीधे प्रभावित होती है, उसमें कमी आ रही है। कृषि जीडीपी में कृषि से जुड़ी गतिविधियों की हिस्सेदारी खासतौर पर सकल मूल्यवर्द्धन, ने फसली खेती को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा मुद्रास्फीति, खासतौर पर खाद्य मुद्रास्फीति भी 2014 और 2015 के सूखे और बाद में कमजोर बारिश के बावजूद स्थिर बनी रही। लब्बोलुआब यह कि अभी आईएमडी के मॉनसून संबंधी पूर्वानुमान के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

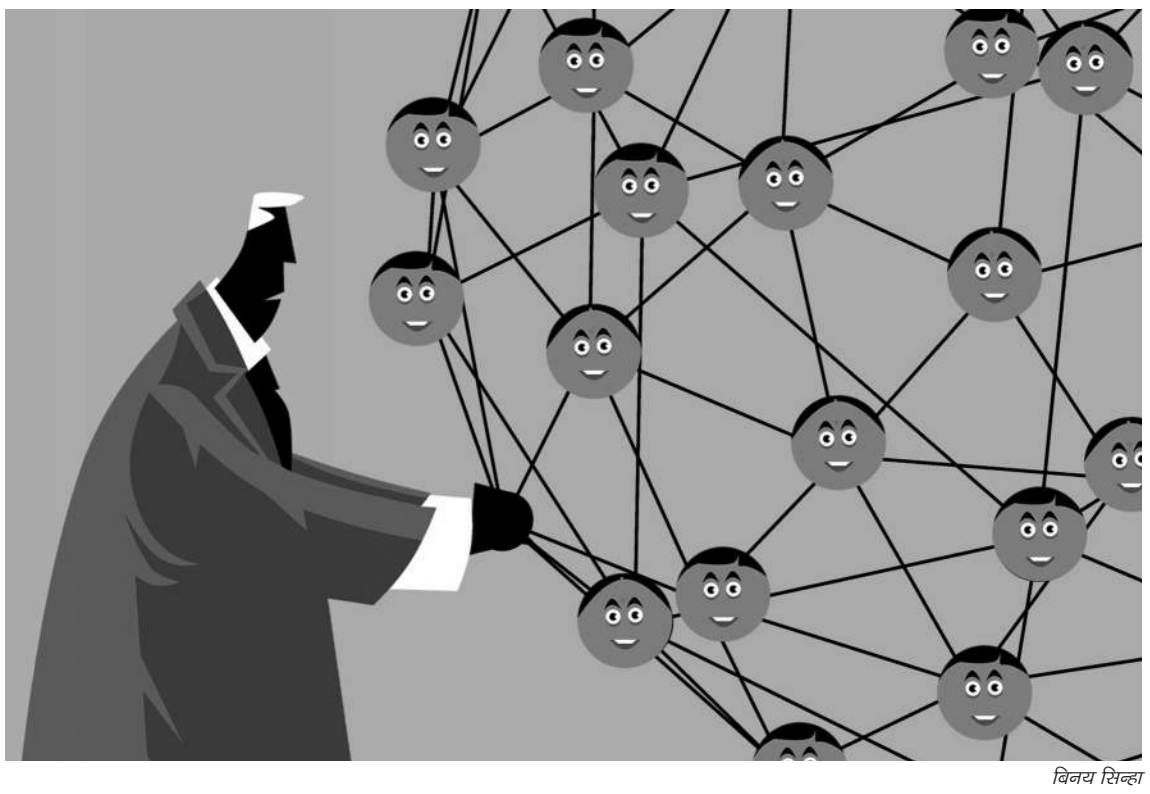

बिनय सिन्हा

नेटवर्क साइंस के जरिये हो रही नई शुरुआत

रोजमर्रा के जीवन के रुझानों का अध्ययन करके शोधकर्ता और वैज्ञानिक एक नई अंतर्दृष्टि दे रहे हैं जो दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **अजित बालकृष्णन**

हर स्कूली बच्चे को यह कहानी अवश्य पढ़ाई गई होगी: 17वीं सदी के मध्य में पूरा इंगलैंड बूबोनिक प्लेग की चपेट में था। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे और 23 वर्षीय आइजक न्यूटन को कैंब्रिज विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा था जहां वह शोधकर्ता थे। उन्हें वापस अपने कस्बे लिंकनशर लौटना पड़ा था जहां वह पैदा हुए और बड़े हुए थे। एक शाम जब मौसम गर्म था तो वह नीचे बगीचे में गए और सेब के एक पेड़ के नीचे बैठे चाय पी रहे थे। तभी एक सेब उनके सर पर गिरा। उन्होंने सोचा कि सेब आखिर नीचे क्यों गिरा? वह दांए-बांए या ऊपर की ओर क्यों नहीं गया? शायद पृथ्वी ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया, इसलिए वह नीचे गिरा। क्या पृथ्वी में कोई ऐसी शक्ति है जो चीजों को अपनी ओर खींचती है? आखिर वह कौन सी ताकत है जो चीजों को अपनी ओर खींचती है? इसी दिशा में सोचते हुए न्यूटन ने गुरुत्व के सिद्धांत की खोज की। यहीं से भौतिक विज्ञान की बुनियाद रखी गई। विज्ञान इसी तरह आगे बढ़ता है। यानी रोजमर्रा के जीवन से चीजों को देखता-समझता हुआ नए सिद्धांत गढ़ता है। बाद में इस सिद्धांत के आधार पर कहीं अधिक व्यापक घटनाओं की व्याख्या की जाती है।

ऐसी ही छोटी-छोटी घटनाओं के आधार पर इन दिनों मानव व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अल्बर्ट लास्लो बारबासी अपनी नई पुस्तक, 'बर्स्ट्स, द हिडेन पैटर्न बिहाइंड एवरीथिंग वी डू, फ्रॉम योर ईमेल टू ब्लडी क्रूसेड्स' में सवाल उठाते हैं, 'क्या हमारे कार्य व्यवहार उन नियमों और व्यवस्थाओं से संचालित होते हैं जो सहजता के मामले में न्यूटन के गुरुत्व नियम के समान हैं।' इस किताब में वह कुछ अप्रत्याशित निष्कर्षों को याद करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने और उनके सहकर्मियों ने ईमेल के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पाया कि इंसान की ईमेल गतिविधियों में अल्पकालिक सघनता के बाद लंबा समय ऐसा भी आता है जब कोई ईमेल नहीं किया जाता। ऐसे में यह अनुमान लगा लेना भी ठीक नहीं है कि इस तरह का तीव्र मानव व्यवहार केवल ईमेल जैसी गतिविधि तक सीमित है। उन्होंने और उनके सहकर्मियों ने पाया कि सन 1905 से 1910 के बीच अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो पत्राचार किया, उसमें भी ऐसे ही लक्षण और रुझान पाए गए।

फिलहाल शोध का एक बड़ा हिस्सा यह समझने का प्रयास कर रहा है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक और साझा रुझान, यानी मनुष्यों के बीच का सोशल नेटवर्क काम करता है। साइटेशन नेटवर्क एक ऐसा रुझान है जो इन दिनों बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

ऐसा तब होता है जब किसी वैज्ञानिक पर्चे का लेखक अन्य पर्चों पर दृष्टि डालता है। अकादमिक जगत में आपकी पदोन्नति या प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों आदि में आपकी नियुक्ति इस बात पर काफी हद तक निर्भर करती है कि आपके कितने शोधपत्र दुनिया की स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। अब शोधकर्ता ऐसे दृष्टांतों का बारीकी से अध्ययन करके उनमें किसी खास रुझान की पड़ताल कर रहे हैं। ऐसा ही एक रुझान 'साइटेशन कार्टेल' के रूप में स्थापित किया गया ताकि वैज्ञानिकों की गुणवत्ता के बीच अंतर किया जा सके। इसके लिए बढ़ते क्रम में अंकों का प्रयोग किया गया है। नेटवर्क के विश्लेषण में यह भी सामने आया कि संपादकों और पत्रों के समूह साथ मिलकर साझा लाभ के लिए काम करते हैं ताकि उनके पत्रों का प्रभाव उत्पन्न करने वाले कारक में इजाफा हो सके तथा अन्य रिश्ते मसलन संपादकों से लेखकों के रिश्ते और लेखकों से लेखकों के रिश्ते मजबूत हो सकें।

नेटवर्क के प्रयोग पर बहुत बड़े पैमाने पर शोध कार्य चल रहा है। दो उदाहरण लें तो वित्तीय नेटवर्क का प्रयोग भेदिया कारोबार का पता लगाने में और आतंकी नेटवर्क को उजागर करने भी किया जा रहा है।

नेटवर्क का ऐसा गहन अध्ययन इस तरह की तकनीक को जन्म दे रहा है जो इस क्षेत्र को उसी स्तर पर ले जा रहा है जो शुरुआती दौर में भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में था। यानी अवधारणा के स्तर पर इन्हें लेकर काफी काम हो रहा है।

किसी नेटवर्क का आकार इस बात से परिभाषित होता है कि उस नेटवर्क में कुल कितने कारक प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तमाम संभावित लिंक का कारकों से भाग देने के बाद हमें उन लिंक का घनत्व अनुपात प्राप्त होता है। जितने लिंक उस कारक से संबद्ध होते हैं, वे उसका अनुपात तय करते हैं। कुलमिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि नेटवर्क विज्ञान के रूप में एक नया विज्ञान उभरकर सामने आ रहा है।

यह विज्ञान हमें यह भी बताता है कि कलाकारों की सफलता के तार भी नेटवर्क में उनकी स्थिति के आधार पर तलाश किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नेटवर्क विज्ञान संस्थान, नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय, बोस्टन के शोधकर्ताओं ने करीब 5 लाख कलाकारों की प्रदर्शनी की नए सिरे से पुनर्रचना की। इस दौरान उन्होंने सहप्रदर्शन नेटवर्क को खंगाला जो विभिन्न संस्थानों के बीच कला गतिविधियों के आवागमन का आकलन करता है। इस नेटवर्क में मुख्यरूप से संस्थागत प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर प्रतिष्ठित केंद्रीय संस्थानों तक जल्दी पहुंच बन जाए तो भविष्य में उच्च प्रतिष्ठित स्थानों पर जाने की संभावना आजीवन बनी रहती है और बहिर्गमन की दर काफी कम हो जाती है। इसके विपरीत, नेटवर्क क्षेत्र के बाहरी दायरे में रहने वालों में बहिर्गमन की आशंका भी अधिक होती है और केंद्रीय संस्थानों तक पहुंच बनने में भी काफी देरी लगती है।

दुनिया भर की सरकारें और वहां के विश्वविद्यालय अपने-अपने यहां नेटवर्क विज्ञान केंद्रों की स्थापना करने में लगे हुए हैं। येल इंस्टीट्यूट फॉर नेटवर्क साइंस उन नेटवर्क का अध्ययन करने में लगा हुआ है जहां बातों का प्रसार जुबानी तौर पर होता है। इसका मकसद है यह देखना कि बातें चर्चा के माध्यम से कैसे आगे बढ़ती हैं।

हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित चिकित्सा को लेकर किए जा रहे शोध पर जोर दे रहा हैं जहां जीव विज्ञान और बीमारियों के क्षेत्र में नेटवर्क की भूमिका, उसकी पहचान और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। हमारे देश में पुणे स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं शोध संस्थान तथा आईआईटी इंदौर स्थित कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स लैब में इसकी शुरुआत के संकेत नजर आ रहे हैं।

सरकार का आकार कम होने के नजर नहीं आ रहे आसार

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

भाजपा और कांग्रेस के वादों में कई समानताएं हैं। परंतु अगली सरकार चाहे जिस राजनीतिक दल की बने, सरकार का आकार छोटा होने की उम्मीद नहीं है। यह वादा हमेशा कागजी ही रहेगा

केंद्र सरकार ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में 9 पेशेवरों को पार्श्विक नियुक्ति दी है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। परंतु इससे एक और बात रेखांकित होती है कि देश की शासन व्यवस्था में सुधार के लिए अभी काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। सच तो यह है न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के वादे के बावजूद बीते कुछ वर्षों के दौरान सरकार की ओर से आकार को कम करने या नौकरशाही में सुधार के लिए कुछ खास नहीं किया गया। ऐसे में यह देखना जानकारीपरक है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के 2019 के चुनाव घोषणापत्र में इस संबंध में क्या वायदा किया गया है। आश्चर्य नहीं कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस दोनों ने एक बार फिर सरकार के आकार को कम करने और उसे प्रभावी बनाने की बात दोहराई है।

भाजपा के घोषणापत्र में वादा किया गया है कि एक समान और पूरक विभागों को क्षेत्रवार मंत्रालयों में विलय किया जाएगा ताकि नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन और तालमेल हो सके। इससे एक ओर नीति निर्माताओं को समग्र और व्यापक नीतियां बनाने का अवसर मिलेगा तो दूसरी ओर क्रियान्वयन सहज हो सकेगा। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की बात को दोहराया है और नौकरशाही में सुधार लागू करने की बात भी कही है।

कांग्रेस के घोषणापत्र में भी यह वादा किया गया है कि पार्टी केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की संख्या कम करेगी। यह कमी उन क्षेत्रों में की जाएगी जिनमें राज्य सरकारें पर्याप्त क्षमता विकसित कर चुकी हैं। भाजपा घोषणापत्र के साथ इन समानताओं के अलावा कांग्रेस ने स्कूल शिक्षा, प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सुविधा, बाल पोषण, पेयजल, स्वच्छता और बिजली वितरण के क्षेत्र में राज्यों को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने की बात कही है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ सहयोगी भूमिका निभाएगी। विडंबना यह है कि दोनों घोषणापत्रों में एक-एक नए मंत्रालय के गठन का वादा भी किया गया है।

भाजपा ने नए जल मंत्रालय के गठन का वादा किया है। उम्मीद की जा रही है कि यह मंत्रालय जल प्रबंधन के कामकाज को समग्र बनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित प्रयासों का बेहतर ढंग से तालमेल किया जा सके। परंतु यह नहीं बताया गया है कि मौजूदा जल संसाधन मंत्रालय का क्या होगा, क्या इसका कामकाज नए मंत्रालय के हवाले हो जाएगा? परंतु घोषणापत्र से यह स्पष्ट है कि नया मंत्रालय राजग की ही पिछली वाजपेयी सरकार की नदी जोड़ परियोजना को देश भर में तेजी से आगे ले जाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पेय जल और सिंचाई के पानी की कोई दिक्कत न हो। न केवल एक नया मंत्रालय बल्कि भाजपा ने एक नए प्राधिकार के गठन के साथ इस दिशा में काम करने का वादा भी किया है।

दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा है कि वह मत्स्यपालन और इससे जुड़े लोगों के लिए नए मंत्रालय का गठन करेगी। उसने मत्स्यपालन और उससे संबंधित लोगों के कल्याण के लिए नैशनल फिशरफॉक कमीशन गठित करने की बात कही है। इसके जरिए कर्ज और फंडिंक की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा।

प्रश्न यह है कि तब कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन आने वाले मौजूदा मत्स्य विभाग का क्या होगा? ऐसा लगता है कि मंत्रालयों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ेगी।

भाजपा और कांग्रेस के घोषणापत्र में एक और साझा बात है आदर्श पुलिस अधिनियम बनाने का वादा। दोनों दल राज्यों के साथ मशविरा करके यह कानून बनाना चाहते हैं। भाजपा को उम्मीद है कि आदर्श पुलिस अधिनियम के जरिए पुलिस को नागरिकों के अनुकूल बनाया जा सकेगा जबकि कांग्रेस का मानना है कि यह प्रस्ताव पुलिस बल को आधुनिक, तकनीक सक्षम और मानवाधिकार तथा विधिक अधिकारों से जोड़ने वाला बनाएगा।

दोनों घोषणापत्र जीएसटी परिषद जैसी प्रणाली के माध्यम से और राज्यों के साथ मशविरा करके विकास को नए-नए क्षेत्रों में ले जाने की बात करते हैं। यह वादा संघवाद के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। भाजपा जीएसटी परिषद के सिद्धांत को अन्य क्षेत्रों में ले जाने का वादा करती है और कहती है कि राज्यों के साथ लेकन नीति निर्माण और शासन के विभिन्न पहलुओं पर काम किया जाएगा। कांग्रेस का वादा है कि वह जीएसटी परिषद की अवधारणा को आगे ले जाकर कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिषद गठित करेगी।

दोनों की समानताएं यहीं समाप्त हो जाती हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वह नीति आयोग को भंग करके उसके स्थान पर कहीं बेहतर योजना आयोग लाएगी, जिसमें 100 से अधिक कर्मचारी नहीं होंगे। कांग्रेस इसके अलावा अनेक नए संस्थान गठित करना चाहती है- उच्च न्यायालयों के निर्णय और आदेशों की सुनाई के लिए छह नए अपीलीय न्यायालय, एक नया पर्यापत पूंजी वाला पर्यटन विकास बैंक ताकि पर्यटन क्षेत्र को पूंजी मिल सके, सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए आयोग तथा कृषि विकास एवं नियोजन पर एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग जिसमें किसान, कृषि विज्ञानी और अर्थशास्त्री शामिल होंगे और कृषि को व्यवहार्य, प्रतिस्पर्धी और लाभकारी बनाने के सुझाव देंगे।

संक्षेप में कहें तो भाजपा और कांग्रेस के वादों में कई समानताएं हैं। परंतु अगली सरकार चाहे जिस राजनीतिक दल की बने, सरकार का आकार छोटा होने की उम्मीद नहीं है। यह वादा हमेशा कागजी ही रहेगा।

कानाफूसी

दस्तानों पर बवाल

अभिनेत्री से राजनेता बनी मिमि चक्रवर्ती, कोलकाता के जाधवपुर से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह हाथों में दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाते देखी जा सकती हैं। यह वीडियो एक चुनाव सभा का है। हाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले मेजर सुरेंद्र पूनिया ने ट्विटर पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि यह दुखद और हताश करने वाला दृश्य है तथा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे लोगों को संसद में नहीं जाना चाहिए। इस पर चक्रवर्ती की सोशल मीडिया टीम तत्काल उनके बचाव में सामने आई और कहा कि पिछले कुछ दिनों के प्रचार अभियान के कारण उनके हाथों में खरोंचे आ गई हैं और जलन हो रही है। यही वजह है कि उन्होंने दस्ताने पहनकर प्रचार अभियान में जाने का निर्णय लिया है।

वोट का खेल

पर्यवेक्षकों का कहना है कि सन 2019 का आम चुनाव सबसे अधिक आक्रामक ढंग से लड़े गए चुनावों में शामिल होगा। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो चुनावी बुखार की चपेट में नहीं आया हो। कोलकाता के बच्चों के बीच 'वोट-वोट' नामक खेल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस खेल के दौरान बच्चों का समूह दो दलों में बंट जाता है और वे हाथ उठाकर प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। एक बार प्रधानमंत्री का चयन हो जाने के बाद सभी उसकी बात सुनते हैं। प्रधानमंत्री के पास कुछ अधिकार होते हैं जिनके तहत यह खेल आगे बढ़ता है। इसके तहत एक समूह को अन्य सदस्यों द्वारा चयनित गीत गाना होता है। इस प्रकार वे एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं।

आपका पक्ष

सीजेरियन प्रसव पर रोक लगे

हाल के वर्षों में देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिए सर्जरी के मामलों में वृद्धि हुई है। प्राकृतिक प्रसव केवल निम्न आय वर्ग से संबंधित परिवारों तक ही सीमित रह गया है। जहां एक ओर अत्यंत निम्न आय वर्ग की महिलाओं को धन के अभाव के कारण आवश्यक हो जाने पर भी सीजेरियन सर्जरी की सुविधा नहीं मिल पाती है और कई मौकों पर वे प्रसव के दौरान ही जीवन गंवा देती हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य और उच्च आय वर्ग में जरूरत नहीं होने के बावजूद सी सीजेरियन सर्जरी के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इस तरह की सर्जरी के बढ़ते मामलों के लिए निजी चिकित्सालयों की बड़ी भूमिका है। कुछ निजी चिकित्सालयों में प्रसव के लिए जरूरी नहीं होने पर भी सीजेरियन यानी सी सेक्शन सर्जरी की सलाह दी जाती है। इसके लिए प्रसूता की जान को खतरा होने का भय दिखाया जाता है। ऐसी स्थिति

में परिजन सीजेरियन डिलीवरी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके एवज में मोटी फीस चुकानी पड़ती है। वहीं अनुभवहीन चिकित्सकों द्वारा समय पूर्व और जबरन कराए शल्य- प्रसव के कारण माता और शिशु दोनों की जान पर बन आती है। एक अध्ययन से पता चला है कि भारत जल्द ही ऑपरेशन से सबसे ज्यादा बच्चे जनने वाला देश बन जाएगा। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार सीजेरियन डिलीवरी के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। एक आंकड़े के अनुसार जनवरी 2015 से दिसंबर 2016 के बीच सीजेरियन सर्जरी के मामलों में 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना आंध्र प्रदेश तथा केरल सबसे आगे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस तरह की सर्जरी की अनुशंसित दर 10 से 15 प्रतिशत होनी चाहिए। वर्तमान में यह दर 17.2 प्रतिशत है तथा 2005 में 8.5 प्रतिशत थी। भारत में वर्तमान मातृत्व मृत्यु दर 130 प्रति लाख है। भारत ने इसे 70 प्रति लाख पर लाने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है कि अवैध तथा गैरजरूरी सीजेरियन डिलीवरी के लिए सर्जरी पर रोक लगाई जाए। इसके लिए देश में शासकीय चिकित्सालयों की व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी। निजी अस्पताल चलाने वाले और मरीजों को जबरन निजी अस्पताल जाने की सलाह देने वाले शासकीय चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्राकृतिक प्रसव को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

सीजेरियन प्रसव के गैरजरूरी इस्तेमाल पर रोक लगाने की जरूरत है

ऋषभ देव पांडेय, कोरबा

न्याय का वादा नहीं धोखा है

यह बेहद अफसोस की बात है कि आजादी के सात दशक बाद भी देश की आधी से ज्यादा आबादी दो वक्त की रोटी के लिए भी तरस रही है। चुनाव के समय तमाम राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार न केवल ऐसे लोगों को न्यूनतम आय देने का भरोसा देते हैं, बल्कि यह भी कहते हैं कि उनके जीतने के बाद बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी लेकिन चुनाव के बाद ये नेता गायब हो जाते हैं। भारत में बढ़ती बेरोजगारी और काफी कम आय पर 10 से 12 घंटे तक काम करने वालों की संख्या में हो रहे इजाफे को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि नेताओं द्वारा किए गए वादे असल में वादा नहीं केवल एक धोखा ही है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।